पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव की आवश्यकता : मुख्यमंत्री

इन विद्यालयों से जुड़ी सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा एक सोसाइटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए

विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाएं, विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य आवश्यक मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें

वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र किन्तु अब तक वंचित वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए, उन्हें यथाशीघ्र पेंशन से लाभान्वित कराया जाए

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की पहुंच तथा प्रभावशीलता और अधिक बढ़ायी जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए

प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ समय से मिलना चाहिए, पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए, छात्रवृत्ति की धनराशि प्रत्येक परिस्थिति में 02 अक्टूबर तक अन्तरित कर दी जाए

लखनऊ : 20 अगस्त, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। इन विद्यालयों से जुड़ी सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा एक सोसाइटी के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि इन आवासीय विद्यालयों का प्रबन्धन और संचालन अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सके।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक में विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं तथा प्रबन्धन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश में 93 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित थे, जबकि वर्ष 2025–26 तक इनकी संख्या बढ़कर 103 हो गई है। इनमें 59 विद्यालय सी0बी0एस0ई0 तथा 44 विद्यालय यू0पी0 बोर्ड से सम्बद्ध हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र किन्तु अब तक वंचित वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए, उन्हें यथाशीघ्र पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। पात्र वृद्धजनों को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े व आवेदन के सत्यापन से लेकर पेंशन स्वीकृति तक की प्रक्रिया समयबद्ध पूर्ण की जाए। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2017–18 में 37.47 लाख से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 67.50 लाख हो गई है। वर्तमान में लगभग 11.50 लाख नए आवेदन लम्बित हैं।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और योजना की पहुंच तथा प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षकों व विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केन्द्रों के माध्यम से संचालित है। इन केन्द्रों पर 1,783 इम्पैनल्ड शिक्षक हैं तथा यू0पी0एस0सी0, पी0सी0एस0, नीट, जे0ई0ई0, एन0डी0ए0 तथा सी0डी0एस0 सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 23,801 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। योजना के अन्तर्गत चार सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स संचालित हैं।

छात्रवृत्ति वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का लाभ समय से मिलना चाहिए। पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और छात्रवृत्ति की धनराशि प्रत्येक परिस्थिति में 02 अक्टूबर तक अन्तरित कर दी जाए।

मुख्यमंत्री जी ने छात्रवृत्ति वितरण में आने वाली तकनीकी और प्रक्रियागत कठिनाइयों का त्वरित समाधान करते हुए पात्र विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि विभिन्न कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित रह गए लगभग 3.16 लाख विद्यार्थियों को पुनः अवसर देने की व्यवस्था की जा रही है। इनमें 31,836 शासकीय, 69,631 अनुदानित तथा 2,46,426 निजी संस्थानों के विद्यार्थी सम्मिलित हैं।

———————

PN-CM-Social Welfare Department- Review Meeting-20 August, 2026